भारत को नेट जीरो पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करना चाहिए?

लेखक- टी. जयरामन

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण) से संबंधित है।

द हिन्दू

27 अक्टूबर, 2021

ऐसा करने से कुछ लोगों द्वारा वैश्विक कार्बन बजट के अति-विनियोग को स्वीकार करना होगा

कई देशों और गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा नेट जीरो अभियान के बावजूद, दुनिया के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का नेट जीरो तक पहुँचने का समय मानवता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर नहीं है। जैसा कि इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की हालिया रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है, दुनिया के औसत तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से पेरिस समझौते में सहमत लोगों तक सीमित करने के लिए वैश्विक कार्बन बजट में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक संचयी उत्सर्जन को सीमित करने की आवश्यकता है।

यह एक सच्चाई है कि इस तरह की सीमा का मतलब है कि अंततः उत्सर्जन शून्य, या अधिक सटीक, नेट जीरो पर लाना चाहिए। लेकिन अपने आप में नेट जीरो तक पहुँचना खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अप्रासंगिक है। यह कहने के अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नल को कब बंद कर देंगे इसका वादा यह गारंटी नहीं देता है कि आप केवल एक निर्दिष्ट मात्रा में पानी निकालेंगे।

नेट जीरो क्या वादे करता है?

अनुमानित संचयी उत्सर्जन के बारे में हम क्या जानते हैं? दुनिया के शीर्ष तीन उत्सर्जक - चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ- अपनी नेट जीरो प्रतिबद्धताओं और 2030 के लिए उनकी बढ़ी हुई उत्सर्जन में कमी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, नेट जीरो से पहले ही 500 बिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर देंगे। ये तीनों अकेले 2020 के बाद से जल्द ही लगभग 500 बिलियन टन की सीमा को पार कर जाएंगे। ऐसे में इन प्रतिबद्ध उत्सर्जन के साथ, 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को बनाये रखने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि यह सीमा तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगी।

न तो पेरिस समझौते और न ही जलवायु विज्ञान में कहीं यह निर्धारित आवश्यकता है कि 2050 तक देशों द्वारा व्यक्तिगत रूप से नेट जीरो तक पहुँचा जाए। पूर्व में इस लक्ष्य की केवल वैश्विक उपलब्धि इतनी ही है कि "सदी के उत्तरार्ध में" यहाँ तक पहुँचा जाए।

दुनिया को 2030 या 2050 तक विशिष्ट लक्ष्यों तक पहुँचना चाहिए ये सभी जलवायु कार्रवाई के लिए विशिष्ट आर्थिक मॉडल के बाइप्रोडक्ट हैं।

ये पेरिस के लक्ष्यों को "सबसे कम लागत" विधियों, पूर्वगामी इक्विटी और जलवायु न्याय द्वारा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस प्रकार के लक्ष्य स्वयं अर्थात विकसित देशों को एक प्रकार से बचाते हैं। अर्थात ये लक्ष्य के माध्यम से विकसित देश, विकासशील देशों पर उत्सर्जन में कमी की आवश्यकताओं को थोपते हैं जबकि ये देश तो पहले से ही कम उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विकसित दुनिया अपने स्वयं के ट्रांजिशन के लिए और समय खरीदने के लिए तथा अपने स्वयं के पिछले उत्सर्जन को छुपाने के लिए इस प्रकर के लक्ष्य सभी पर सार्वभौमिक रूप से थोप देते हैं।

2020 के बाद भविष्य के संचयी उत्सर्जन पर ये कठोर सीमाएं, जो कुल वैश्विक कार्बन बजट के पांचवें हिस्से से भी कम है, वैश्विक उत्तर देशों अर्थात विकसित देशों द्वारा अतीत में इसके काफी अधिक विनियोग का परिणाम है। दुनिया के पांचवें हिस्से से भी कम पिछले सभी संचयी उत्सर्जन के लिए केवल तीन देश ही कुल के पांचवें हिस्से के लिए जिम्मेदार रहा है, अकेले अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 45% का योगदान दिया है। इसलिए पश्चिमी विश्व की नेट जीरो की अवधारणा को सबके लिए समान बना देना सही नहीं है।

भारत को क्या करना चाहिए

भारत की उत्सर्जन कहानी को शीर्ष तीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। भारत पूर्व-औद्योगिक युग से कार्बन डाइऑक्साइड के 4.37% से अधिक संचयी उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार नहीं है, भले ही यह जनसंख्या के स्तर पर बहुत बड़ा देश है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व औसत के आधे से भी कम है, अमेरिका के 1/8 गुनें से भी कम है, और चीन में 2000 के बाद की तरह कोई वृद्धि नहीं हुई है।

भारत के लिए अब नेट जीरो घोषित करना वैश्विक कार्बन बजट के कुछ और अधिक विनियोग को स्वीकार करना है। वैश्विक उत्सर्जन में भारत का योगदान, स्टॉक और प्रवाह दोनों में, इतना कम है कि उसकी ओर से कोई भी बलिदान दुनिया को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। न ही यह इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकता है कि विकसित दुनिया और चीन भविष्य में अपने उत्सर्जन को और सीमित कर देंगे। यदि ऐसी अपेक्षाओं को झुठला दिया गया, तो यह अपनी ही आबादी के भविष्य को खतरे में डाल देगी, और इसे अभूतपूर्व कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। 2020 से पहले के अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए विकसित दुनिया की विफलता के साथ-साथ इसे स्वीकार करने से इनकार करने से भविष्य के लिए थोड़ा विश्वास मिलता है।

वैश्विक कार्बन बजट विकसित देशों को अतीत और वर्तमान में इसका पूरी तरह से दोहन करने की अनुमति देने वाले किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं है। बाकी हिस्सों में से केवल चीन ही इस बाधा को पार करने में कामयाब रहा है। भारत को, प्रबुद्ध स्वार्थ में, अब वैश्विक कार्बन बजट के उचित हिस्से के लिए अपना दावा पेश करना चाहिए। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वित्तीय सहायता, "नकारात्मक उत्सर्जन" के साथ, यदि उत्तरार्द्ध में सफल होता है, तो अतीत के नुकसान की भरपाई कर सकता है। इस तरह के दावे के अभाव में, शमन के लिए भारत के काफी मौजूदा प्रयास एक व्यर्थ प्रयास हैं, जो केवल कुछ लोगों द्वारा वैश्विक कॉमन्स के निरंतर अति-शोषण के लिए रास्ता आसान बनाते हैं।

भारत द्वारा इस तरह का दावा इसे अधिक से अधिक, और बहुत आवश्यक दीर्घकालिक विकल्प प्रदान करता है। यह कोयले, इसके प्रमुख जीवाश्म ईंधन संसाधन, और तेल और गैस के जिम्मेदार उपयोग को निम्न मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति से बाहर निकालने और अच्छे के लिए गरीबी, भूख और कुपोषण को मिटाने में सक्षम बनाता है।

भारत का संसाधन-संपन्न लघु उद्योग क्षेत्र, जो कृषि के बाहर अधिकांश आबादी को रोजगार और आजीविका प्रदान करता है, को विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। ऊर्जा के बाद भारत के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कृषि क्षेत्र को अपनी उत्पादकता और किसानों की आय को दोगुना करने और लचीलापन बनाने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के लिए भविष्य में अनुकूलन के लिए सामान्य रूप से जलवायु लचीलापन के लिए बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। इन सभी के लिए कार्बन बजट के उचित हिस्से के माध्यम से उपलब्ध कराए गए कम से कम सीमित जीवाश्म ईंधन संसाधनों की आवश्यकता होगी।

दूसरी ओर, विकसित देश और चीन, यदि वे पेरिस समझौते के लक्ष्यों के बारे में गंभीर हैं, तो उन्हें 2050 से पहले शुद्ध शून्य तक पहुँच जाना चाहिए। 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए, शेष दुनिया के लिए अधिक जगह है, क्योंकि संचयी इसके लिए उत्सर्जन की सीमा, समान विषमताओं के साथ, 1,350 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि, बड़े उत्सर्जकों द्वारा अपने भविष्य के संचयी उत्सर्जन, वैश्विक कार्बन बजट के उनके उचित हिस्से और उनके अनुरूप तापमान लक्ष्य को स्पष्ट किए बिना, भारत नेट जीरो पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है।

भले ही भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने अल्पकालिक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को व्यवहार में बढ़ाना था, जो अब तक अनावश्यक है, उसे वैश्विक कॉमन्स के अपने हिस्से का दावा करते हुए ऐसा करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि इसके प्रयास विकसित दुनिया की मुक्त सवारी को और सक्षम नहीं बनाएंगे और भारत के औद्योगिक और विकासात्मक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन तक इसकी पहुँच की रक्षा करेंगे।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. नेट जीरो की अवधारणा में कार्बन उत्सर्जन को अधिकतम किस वर्ष तक जीरो तक लाना है?

(a) 2020

(b) 2030

(c) 2040

(d) 2050

Expected Question (Prelims Exams)

Q. In the concept of Net Zero, by which year the maximum carbon emissions have to be brought to zero?

(a) 2020

(b) 2030

(c) 2040

(d) 2050

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. नेट जीरो की अवधारणा क्या है? क्या यह अवधारणा विकसित देशों के हितों के अनुकूल तथा विकासशील देशों पर थोपी गयी है? टिप्पणी करें। (250 शब्द)

Q. What is the concept of Net Zero? Is this concept suited to the interests of developed countries and imposed on developing countries? make a comment. (250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।